

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर, तर्ष 22, अंक - 346- रविवार 18- अक्टूबर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

RNI Reg.No.-CHHIN/2004/15050,डाक पंजीकरण. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सक्षिप्त समाचार

कांग्रेस की 1 नवंबर को रामलीला मैदान में जनसभा

पुलिस ने 25 अक्टूबर से 3 तारीख तक के लिए दी अनुमति



नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026। इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक जनसभा आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी ने दिल्ली पुलिस से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। दिल्ली पुलिस ने निर्धारित विरोध स्थल पर जनसभा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 की अवधि के लिए जारी की गई है। दिल्ली पुलिस लगातार आयोजकों के साथ संपर्क में है। इसके अतिरिक्त, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उचित कानून-व्यवस्था व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। साथ ही, प्रभावी यातायात प्रबंधन और प्रस्तावित जनसभा का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना भी है। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया, 'जैसा की ज्ञात है कि सीबीडी ग्राउंड, बुराड़ी मैदान और रामलीला मैदान, यह तीनों रैली और प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बताए गए हैं। इसके तहत अभी कांग्रेस पार्टी ने हमसे संपर्क किया। कांग्रेस पार्टी ने एमसीडी से 25 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक रामलीला मैदान की उपलब्धता का पता किया और उन्हें बताया गया कि उस दौरान ये स्थल खाली है।

भारत को बड़ी राहत...

ट्रंप ने रूसी तेल खरीद पर लगने वाले 100% टैरिफ से दी छूट



नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध से जुड़े 'ग्राहम कानून' के तहत लगने वाले प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों से छूट देने का कार्रकारी आदेश जारी किया है। आदेश 16 अक्टूबर का है और इसके ठीक दो दिन बाद, 18 अक्टूबर से, ये शुल्क लागू होने थे। रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में भारत भी शामिल है, इसलिए इस फैसले को भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। ट्रंप ने आदेश में लिखा है कि वे ग्राहम कानून में दिए गए प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों के लागू होने से छूट दे रहे हैं, और इस समय ऐसी छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने इस आशय का प्रमाण-पत्र और उसका आधार बताने वाली रिपोर्ट अमेरिकी संसद को सौंपी है। आदेश की बनावट खुद में दिलचस्प है। इसकी धारा 2 में शुल्क की दरें तय की गई हैं और धारा 4 में उन्हीं शुल्कों पर छूट दे दी गई है। यानी कागज पर शुल्क मौजूद हैं, पर फिलहाल वसूल नहीं जाएंगे। आदेश की धारा 3 के तहत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को विदेश, वित्त और ऊर्जा मंत्रियों के साथ मिलकर इस बात पर नजर रखनी है कि कौन से देश रूसी मूल का कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं और कौन प्रतिबंधों से बचाव में मदद कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्ट देनी है और ऐसी किसी भी स्थिति की तुरंत जानकारी देनी है। जिससे आगे कार्रवाई की जरूरत लग सकती हो- इसमें छूट पर पुनर्विचार भी शामिल है। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि रूस को लेकर पहले से लागू आपातकाल संबंधी कार्यकारी आदेशों के तहत जो प्रतिबंध हैं, उन पर इस छूट का कोई असर नहीं पड़ेगा।

बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका, बाल यौन शोषण कंटेंट हटाने के लिए डेटाबेस बने : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है

कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना हर व्यक्ति, यहां तक कि बच्चों का भी मौलिक अधिकार है। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना बेतुका होगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और उनकी आजादी दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा... इंटरनेट पर गलत कंटेंट होने के कारण बच्चों के लिए इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाना सही नहीं है। ऐसी रोक से बच्चे कम सुरक्षित वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। ऑनलाइन धमकी या शोषण का सामना करने वाले बच्चे शिकायत करने से भी डर सकते हैं। कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट को पहचानने और हटाने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र को नेशनल डेटाबेस बनाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसा कंटेंट हटाने के दो घंटे के भीतर पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को रिपोर्ट देनी होगी।

5 साल में बच्चों की अश्लील सामग्री से जुड़े मामले 26.6 गुना बढ़े

गृह मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में पेश एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, बच्चों की अश्लील तस्वीरों और वीडियो से जुड़े मामले 2018 में 44 थे, जो 2022 में बढ़कर 1,171 हो गए। यानी 26.6 गुना बढ़े। वहीं, बच्चों के खिलाफ दर्ज साइबर अपराध के मामले 2018 में 232 थे, जो 2022 में बढ़कर 1,823 हो गए। हालांकि, केंद्र ने 2022 के बाद का डेटा रिलीज नहीं किया।

रकूली पड़ई में शामिल लेवी ऑनलाइन सुरक्षा

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तकनीकी इंतजाम बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए काफी नहीं है। बच्चों को ऑनलाइन खतरों को पहचानना, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखना और गलत व्यवहार होने पर मदद मांगना भी सिखाना जरूरी है। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सहमति, स्वस्थ रिश्तों, सुरक्षित और असुरक्षित स्पेश, ऑनलाइन शोषण और उसकी शिकायत करने के तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए। कोर्ट ने नेशनल कार्टिसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और राज्य की शैक्षिक संस्थाओं से कहा कि वे बाल मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों और अभिभावक विशेषज्ञों की मदद से पड़ई की सामग्री तैयार करें।

डेटाबेस में कंटेंट की जांच के लिए होंगे ये इंतजाम

जरिस्टस जैबी पारदीवाला और जरिस्टस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने डेटाबेस में दर्ज सामग्री की सही पहचान करने के लिए कई निर्देश दिए हैं।

■ **फोटो-वीडियो की डिजिटल पकड़ होगी दर्ज** : डेटाबेस में कंटेंट का डिजिटल हैश और उस वेबसाइट का लिंक रखा जाएगा, जहां वह मौजूद है।

■ **तीन विशेषज्ञ करेंगे जांच** : सामग्री को डेटाबेस में जोड़ने से पहले कम से कम तीन प्रशिक्षित विशेषज्ञ परस्पर रूप से जांचेंगे कि वह बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी है या नहीं। शुरुआती जांच में सॉफ्टवेयर की मदद ली जा सकती है।

■ **दोबार अपलोड होने पर भी पहचान होगी** : सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट का डेटाबेस से मिलान कर सकेंगी। सामग्री दूसरे प्लेटफॉर्म पर दोबार अपलोड होने पर भी पहचानी जा सकेगी।



पेड़ और सव्सक्रिप्शन वाली सेवाओं की भी जांच होगी

कोर्ट ने पेड़ और सव्सक्रिप्शन वाली वेबसाइटों और सेवाओं की सख्ती से जांच करने को कहा है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा या अन्य प्रतिबंधित कंटेंट न दिखाया जाए और न फैलाया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी विचार करने को कहा है कि ऐसी सामग्री से कमाई गई रकम जब्त करके वापस ली जा सकती है या नहीं।

केंद्र सरकार को 10 दिसंबर तक देनी होगी रिपोर्ट

केंद्र सरकार को कोर्ट के निर्देश लागू करने के लिए जरूरी नियम और काम करने का तरीका तय करना होगा। जरूरत पड़ने पर आईटी कानून और नियमों में बदलाव भी करने होंगे। सरकार को हलफनामा देकर बताया होगा कि निर्देशों पर अब तक क्या काम हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए



श्रीनगर, 17 अक्टूबर

2026। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शनिवार सुबह आतंकिओं और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक दो आतंकी मारे गए हैं। पहले इस घटना को घुसपैठ की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे या नहीं। सेना के मुताबिक, कुपवाड़ा स्थित केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे सुरक्षाबलों ने सदिग्ध गतिविधि देखी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। सचं ऑपरेशन अभी जारी है।

बांग्लादेश के रिजॉर्ट में आग, 10 की मौत

बिना फायर सेफ्टी लाइसेंस के रिजॉर्ट चल रहा था

ढाका, 17 अक्टूबर 2026। बांग्लादेश के कांक्स बाजार जिले में शनिवार सुबह समुद्र किनारे बने एक रिजॉर्ट में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। आग सुबह करीब 7:25 बजे टुपटुप रेस्टो एंड रिजॉर्ट में लगी। तीन मंजिला लकड़ी की इमारत आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हदसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। रिजॉर्ट के पास आग से बचाव के इंतजामों की मंजूरी नहीं थी। जून में चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने इसे लेकर चेतावनी भी दी थी।

शांट सर्फिंट की वजह से आग लगने की आशंका : अधिकारियों के हवाले से बताया है कि बिजली के तारों में शांट सर्फिंट से आग लगी थी। इसके



बाद यह आग एयर कंडीशनर में लगी। गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह का पता चल सकेगा। आग लगने के समय रिजॉर्ट में करीब 30 लोग मौजूद थे। इनमें से 4 से 5 लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाकी लोगों के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।

असहमति के साथ सम्मान जरूरी, फैसला देने से पहले सुनें : सूर्यकांत

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को लॉ स्टूडेंट्स से कहा कि आप किसी के साथ असहमत हो सकते हैं लेकिन उसकी गरिमा बनाए रखें। कोई भी फैसला देने से पहले सामने वाले को भी सुनें। चीफ जस्टिस नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के 34वें एनुअल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानूनी शिक्षा सिर्फ एकेडमिक नॉलेज तक सीमित नहीं होनी चाहिए। छात्रों को अलग-अलग विचारों को समझना जरूरी है। इससे पहले यूनिवर्सिटी के 700 से ज्यादा मौजूद और पूर्व छात्रों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई



थी। इसके चलते 27 अगस्त को यूनिवर्सिटी ने 12 सितंबर को होना वाला दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया था। हालांकि, पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने दीक्षांत समारोह रद्द करने का अपना फैसला वापस ले लिया।

न्याय के लिए खड़े होने का साहस जरूरी : कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल आपराधिक या संवैधानिक कानून के सिद्धांतों को सीखना नहीं है। इसका मकसद ऐसे लोगों से संवाद करने का अनुभव

हासिल करना भी है, जो दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देखते हैं। कानून और न्यायिक फैसलों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। न्याय के लिए खड़े होने का साहस और अनुसूची आवाजों की चिंताओं को सुनने की विनम्रता भी जरूरी है।

समाज में योगदान देने की भी जरूरत है : छात्रों को अपने सिद्धांतों से समझौता करने और प्रोफेशनल लाइफ में शांति के बचाव चाहिए। कानूनी पेशे के जरिए अन्याय को दूर करने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और सौविधान को बनाए रखने से वकीलों को संतुष्टि मिल सकती है। राष्ट्र हमसे सिर्फ कानून के पेशेवर के तौर पर नहीं, बल्कि समाज में योगदान देने की भी उम्मीद करता है।

जनगणना में गणनाकारों की पात्रता बढ़ाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2026। कांग्रेस ने जनगणना-2027 के लिए गणनाकारों की नियुक्ति के पात्रता नियमों में बदलाव को लेकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसके जरिए एक ही विचारधारा के हजारों कार्यकर्ताओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। इससे जनगणना की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। पार्टी ने इस संबंध में 16 अक्टूबर को जारी अधिसूचना को संच के प्रशिक्षण कार्यक्रम और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकीय परिवर्तन समिति की गतिविधियों के संदर्भ में देखने की बात कही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने

शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। शिविर में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने 14 अक्टूबर को जनसांख्यिकीय परिवर्तन संबंधी उच्चस्तरीय समिति की ओर से आम लोगों और भारतीय एवं विदेशी संगठनों से सुझाव मांगे जाने का भी उल्लेख किया। रमेश ने आरोप लगाया कि इन घटनाक्रमों को जनगणना के लिए गणनाकारों की पात्रता बढ़ाने के फैसले से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

राजस्थान : भोपाल से खाटूश्याम जा रही मिनी बस नाले में गिरी...8 की मौत और कई घायल

कोटा, 17 अक्टूबर 2026। राजस्थान के कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। 25 से अधिक यात्रियों से भरी एक मिनी बस (टेम्पो टैक्लर) अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 15 फीट नीचे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। सीटों के बीच फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए आसपास के ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि हादसे में आठ लोगों की मौत गई है। घायलों को जिला मुख्यालय लाया गया है। पुलिस के अनुसार, हादसा शनिवार सुबह करीब छह बजे सिमलिया थाना क्षेत्र में कराड़िया टोल से कुछ किलोमीटर दूर हुआ। टेम्पो टैक्लर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खाटूश्याम के दर्शन के लिए जा रहा था। इसमें 25 से



अधिक यात्री सवार थे, जिनमें कई लोग मध्य प्रदेश के बैतुल जिले के रहने वाले बताए गए हैं। अचानक बस पुलिया से नीचे नाले में गिर गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आगे की सीटों पर बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें

और बचाव दल भी मौके पर पहुंचे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जेठा के अनुसार, हादसे में मृतकों और घायलों की पहचान कर ली गई है। मृतकों में अरुणा, वैष्णवी, त्रिशा, कृष्णा, अनिता, ओम सूर्यवंशी और राज के नाम सामने आए हैं। बस चालक की भी मौत हो गई है। इस तरह हादसे में कुल आठ लोगों की जान गई।

घायलों में वंदिता, अजय गांवडे, वेदांत झरबड़े, मोहनिस झरबड़े, आकांक्षी झरबड़े, हेमलता गायकवाड़ और सारांश सहित अन्य यात्री शामिल बताए गए हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई होगी। हालांकि, हादसे के वैज्ञानिक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

नोएडा में एक ही परिवार के पांच लोगों की सद्विध अवस्था में मौत, फूड प्लाजनिंग की आशंका...

नोएडा, 17 अक्टूबर 2026। उतर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर नोएडा में थाना रबुपुरा क्षेत्र के ग्राम नगला श्री पदम में रहने वाले एक ही परिवार के पांच लोगों की सद्विध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस को आशंका है कि उनकी मौत फूड पॉजनिंग के चलते हुई है। पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह थाना रबुपुरा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम नगला श्री पदम निवासी एक ही परिवार के पांच सदस्यों महेश (37) पुत्र कृष्णा, ललित (35) पत्नी महेश, लड्डू (11) पुत्र महेश, मिट्ठी (07) पुत्री महेश, साक्षात (03) पुत्र महेश मृत अवस्था में अपने घर पर पड़े हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एंबुलेंस व फूड एंड



सेफ्टी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किये जा रहे हैं। मृतकों के शव को कब्जे में

लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फूड प्लाजनिंग का लग रहा है। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया है कि मृतकों ने रात को नूट्रिशन खाया था।

जगराते के लिए बांधी रस्सी से बाइक टकराई, फैजान की मौत जयस्तंभ चौक पर हादसे के बाद बवाल,परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप,पूजा समिति के पदाधिकारियों समेत अन्य पर अपराध दर्ज...

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।
 शहर के जयस्तंभ चौक के पास शुक्रवार शाम जगराता कार्यक्रम के लिए की गई बैरिकेडिंग से बाइक टकराने पर 20 वर्षीय युवक मो. फैजान की मौत हो गई,जबकि उसका साथी समीर घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने देर रात कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया। परिजनों ने रास्ते में बांधी गई रस्सी और जीआई तार से हदसा होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूजा समिति के पदाधिकारियों समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, जयस्तंभ चौक के पास जागृत नव युवक मंडल हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन करता है। शुक्रवार रात जगराता होना था,जिसकी तैयारी में समिति के सदस्य जुटे थे। लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पूजा पंडाल से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। शाम करीब 7 बजे मायापुर निवासी मो. फैजान अपने साथी समीर के साथ बाइक से अग्रसेन चौक से महामाया चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान जयस्तंभ चौक के पास उनकी बाइक बैरिकेडिंग से टकरा गई। हादसे में फैजान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि समीर को भी चोटें आईं। समिति के सदस्यों ने



फैजान को ओंटो से अस्पताल पहुंचाया,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
परिजनों का आरोप..गले में फंसी थी रस्सी : मृतक के परिजनों का आरोप है कि रास्ता रोकने के लिए बांधी गई रस्सी और जीआई तार फैजान के गले में फंस गए थे। मौके पर पहुंचने पर उसके गले में रस्सी और तार फंसे होने तथा काला निशान पड़ने की बात भी परिजनों ने कही। उन्होंने करंट लगने की आशंका भी जताई है। परिजनों ने रात के अंधेरे में रस्सी दिखाई नहीं देने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने को हादसे की वजह बताया।
देर रात कोतवाली पहुंचे परिजन : घटना से आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने देर रात कोतवाली पहुंचकर विरोध



समिति का दावा...तेज रफतार में थी बाइक

जागृत नव युवक मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि जगराता कार्यक्रम के लिए अग्रसेन चौक के पास भी बैरिकेडिंग की गई थी,जहां यातायात विभाग की महिला आरक्षक तैनात थीं। बाइक सवारों को उस रास्ते से जाने से रोका गया था। समिति के अनुसार,हादसे वाली जगह पर भी बांस, रस्सी और बैरिकेडिंग लगाई गई थी। बाइक की रफतार इतनी तेज थी कि टक्कर से चैनल गेट उखड़ गया। पदाधिकारियों ने दावा किया कि रस्सी करीब तीन फीट की ऊंचाई पर बंधी थी और युवक के गले में रस्सी या तार नहीं फंसा था। उनके मुताबिक,बैरिकेडिंग से टकराने के कारण सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हुई। हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

जताया। उन्होंने जागृत नव युवक मंडल और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सुरेश कन्नौजिया,संदीप अग्रवाल

समेत अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1),125(ए) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

कक्षाओं से लेकर सुरक्षा तक,बदलेगी पीजी कॉलेज की तस्वीर 15 नई कक्षाएं होंगी उपलब्ध,सीसीटीवी निगरानी और गणवेश अनिवार्य कर अनुशासन सुधारने की पहल

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों और कमियों को दूर करने की दिशा में पहल शुरू की गई है। महाविद्यालय प्रशासन आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटा है। पिछले कुछ महीनों में शुरू किए गए प्रयासों के तहत नए कक्षाओं का निर्माण, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, गणवेश और पहचान पत्र की अनिवार्यता सहित कई व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। महाविद्यालय में कक्षाओं की कमी लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए विभिन्न मंदा से नए कक्षाओं का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आगामी कुछ महीनों में लगभग 15 अतिरिक्त कक्षाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे विद्यार्थियों को राहत मिलने के साथ शिक्षण व्यवस्था को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार की रूसा योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में मल्टीपर्पज गर्ल्स सेंटर का निर्माण भी प्रगतिरत है। इसमें छात्राओं के लिए कौशल प्रशिक्षण,शारीरिक फिटनेस,विज्ञान एवं तकनीकी डिजिटल सुविधाओं,सम्मेलन और कोचिंग सेंटर,रीडिंग हॉल,विधिक सहायता तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए केंद्र विकसित किए जाने की योजना है। इसके साथ ही सेल्फ डिफेंस सेंटर, छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय एवं वांशरूम और दो कार्यालयों की सुविधा भी प्रस्तावित है।



सीसीटीवी निगरानी से सुरक्षा पर जोर : महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था की गई है। वहीं, विद्यार्थियों के लिए गणवेश अनिवार्य करने के साथ सभी को महाविद्यालय की ओर से पहचान पत्र जारी किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे विद्यार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और संस्थान में अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
छात्रावास और परिसर की व्यवस्था में सुधार : महाविद्यालय के छात्रावासों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अनुशासन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम एवं व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अनुशासन समिति के सदस्यों को नियमित रूप से परिसर का भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं,ताकि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अनुशासन से जुड़े मामलों पर निगरानी रखी जा सके। स्थानीय जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ समन्वय कर महाविद्यालय में मरम्मत कार्य भी कराए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में दीपावली अवकाश अब 6 दिन का, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश प्रदेश के स्कूलों में 6 से 11 नवंबर तक रहेगा दीपावली अवकाश

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।
 छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए पूर्व में घोषित दीपावली अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब कुल 6 दिनों का अवकाश घोषित किया है। संशोधित आदेश के अनुसार प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा डी.एड., बी.एड., एम.एड. महाविद्यालयों में 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक दीपावली अवकाश रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार पूर्व में 21 सितंबर 2026 को जारी शैक्षणिक कैलेंडर में दीपावली अवकाश 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक कुल 5 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था। राज्य शासन ने उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दीपावली अवकाश की अवधि एक दिन बढ़ाकर 11 नवंबर 2026 तक कर दी है। इस निर्णय से प्रदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थानों को दीपावली पर्व के अवसर पर एक अतिरिक्त दिन का अवकाश मिलेगा।



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।
 शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल है। शहर में 500 से अधिक पूजा पंडालों में मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। वहीं, विभिन्न समितियों की ओर से डांडिया,गरबा और जगराते के आयोजन भी किए जा रहे हैं।



शुक्रवार रात शहर के अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति गीतों और संगीत पर झूमते रहे। सरगांव पैलेस रिसॉर्ट में आयोजित डांडिया कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह शामिल हुईं। उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं, अटल विहार कॉलोनी सरगांव में जगराते का आयोजन किया गया। संस्कृति



विभाग के सौजन्य से पारंपरिक लोक कला मंच चमेली गौदा के कलाकार रामलल्लू पांडेय और उनकी टीम ने भोजपुरी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी धार्मिक गीतों की प्रस्तुति दी। मुख्य कलाकार रामलल्लू पांडेय ने छत्तीसगढ़ी देवी जसगीत 'आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना हो' की शानदार प्रस्तुति दी। गीत पर श्रोता झूम उठे। कलाकारों ने रातभर एक से बढ़कर एक

बच्चों ने देवी-देवताओं का रूप धरकर मोह मन

जगराते के दौरान कॉलोनी के बच्चों ने भगवान गणेश, श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता, मां काली, भगवान शंकर और मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी-देवताओं का रूप धारण किया। बच्चों की आकर्षक वेशभूषा कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही।

जिले के 35 शासकीय स्कूलों में नीट एवं जेईई की ऑनलाइन कोचिंग शुरू, मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया शुभारंभ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता : मंत्री अग्रवाल



जिले के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बेहतर अवसर उपलब्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

ए-हेल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 166 पशु सखियों को तैयार किए गए प्रमाण-पत्र

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला खनिज संस्थान न्यास एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के 35 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नीट एवं जेईई लाइव ऑनलाइन कोचिंग का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह शैक्षणिक परियोजना का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को उनके सपनों को नई उड़ान देने का अवसर है, उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव है। शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना

हमारी प्राथमिकता है। इस ऑनलाइन कोचिंग पहल से विद्यार्थियों को विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। हमारा मानना है,प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। उचित अवसर मिले, उचित मार्गदर्शन मिले और मेहनत करने का हौसला हो,तो सरगुजा का बच्चा भी देश में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने प्राचार्यों को कोचिंग में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पालकों को इस हेतु प्रेरित करने कहा। उन्होंने बच्चों को कहा कि सफलता हासिल करने के लिए अनुशासन और व्यवहार भी बहुत जरूरी है। आप बड़े सपने देखिए, उसे पूरा करें और देश-प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

संसद चिन्तामणि महाराज ने कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आज का समय प्रतियोगिता का समय है,ऐसे समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की यह पहल सराहनीय पहल है। उन्होंने बच्चों को कड़ी मेहनत करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा कि लुप्त विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए यह महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मन लगाकर अपनी क्षमता का शत-प्रतिशत प्रयोग करने प्रोत्साहित किया। राज्य युवा आयोग के

अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि इस पहल के लिए सरगुजा जिला आइडल जिला होगा,यह परियोजना पूरे प्रदेश में लागू हो हमारा प्रयास रहेगा। यह युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा, उन्होंने बच्चों को कठिन परिस्थितियों से निक्कलकर आगे बढ़ने प्रेरित किया। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि जिले के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रभावी क्रियाचयन सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों की प्रगति को नियमित निगरानी की जाएगी,ताकि इस पहल का अधिकतम लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 एवं 2027-28 के दौरान कक्षा 11वीं के विज्ञान संकाय के लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक लाइव ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके माध्यम से गणित एवं जीव विज्ञान समूह के विद्यार्थी जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। वहीं प्रत्येक तीन माह में एक फीडबैक सेशन भी रखा जाएगा।

इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्यों एवं विद्यार्थियों ने निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए शासन- प्रशासन को धन्यवाद दिया। लाइव ऑनलाइन कक्षाओं और आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम से होगी नीट एवं जेईई की तैयारी- परियोजना का क्रियाचयन का फिजिक्स वाला लिमिटेड एजेंसी द्वारा की जाएगी। सभी 35 विद्यालयों में एक साथ लाइव टू-वे इंटरैक्टिव कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी के

मिश्रित माध्यम में संचालित होने वाली इन कक्षाओं से विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों की तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर, मोबाइल ऐप एवं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्लास नोट्स,मुद्रित अध्ययन सामग्री,प्रश्न बैंक, ऑनलाइन मॉक टेस्ट तथा ऑन-डिंडिया टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं भी शामिल है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने के लिए एआई आधारित लर्निंग एनालिटिक्स,प्रदर्शन ट्रेकिंग एवं अभिभावक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में आधुनिक तकनीक से युक्त स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए 75 इंच के 43 इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, कंप्यूटर सिस्टम,वायरलेस माइक्रोफोन,एचडी वैंब कैमरा,स्पीकर सिस्टम तथा कम से कम तीन घंटे का पावर बैकअप उपलब्ध कराया गया है।

पशु सखियों को वितरित किए गए प्रमाण-पत्र—इस अवसर पर ए-हेल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 166 पशु सखियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली पशु सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर पशुधन टीकाकरण, कुमिनाशक दवा वितरण और पशु बीमा जैसे कार्यों में फील्ड पर मदद करेंगी। इस सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरसेटी, कृषि विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सा विभाग का विशेष सहयोग रहा। इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुधन के स्वास्थ्य, देखभाल और सुरक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

नॉकआउट फुटबॉल में बलसेड़ी परसोढ़ी और मेंड्रा ने दर्ज की जीत

दो मुकाबलों का फैसला टाईब्रेकर से...तीसरे मैच में मेंड्रा ने 1-0 से मारी बाजी



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

गांधी स्टेडियम में खेली जा रही संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 के दूसरे राउंड में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। तीन मैचों में बलसेड़ी, परसोढ़ी और मेंड्रा की टीमों ने जीत दर्ज कर अगले दौर की ओर कदम बढ़ाए। पहले दो मुकाबलों का फैसला टाईब्रेकर से हुआ, जबकि तीसरे मैच में मेंड्रा ने 1-0 से जीत हासिल की। दिन का पहला मुकाबला बलसेड़ी और बड़नी झरिया के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने पहले हाफ में बेहतर तालमेल के साथ खेलते हुए गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों गोल करने में नाकाम रहें। इसके बाद टाईब्रेकर में बलसेड़ी ने 4-3 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। दूसरे मुकाबले में पीजी रॉयल अम्बिकापुर और परसोढ़ी की टीमें आमने-सामने थीं। दोनों टीमों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी गोल नहीं कर

सकी। मैच का निर्णय टाईब्रेकर से हुआ,जिसमें परसोढ़ी ने 5-4 से जीत दर्ज की।
मेंड्रा ने गुमगारा को 1-0 से दी शिकस्त : दिन के तीसरे मुकाबले में गुमगारा और मेंड्रा के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों गोल नहीं कर सकीं। दूसरे हाफ में मेंड्रा ने एक गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। अंतिम समय तक गुमगारा की टीम बराबरी नहीं कर सकी और मेंड्रा ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैचों में निर्णायक की भूमिका ललित किशोर, आरुण और रामबहादुर लांबा ने निभाई। प्रतियोगिता के दौरान कार्यकारिणी सदस्य दीपक कुजूर, कमलेश क्रिसोष्ट, अखिलानंद, विनोद पैकरा और मंगल उपस्थित रहे।
18 अक्टूबर को होंगे तीन मुकाबले : प्रतियोगिता में 18 अक्टूबर को तीन मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला एमएफसी कपरास और शंकरगढ़ के बीच, दूसरा एफसी कर्मयोगी और कोटेया के बीच तथा तीसरा सरगुजा इलेवन और अम्बिकापुर यूनाइटेड के बीच होगा।

लखनपुर में चोरों का बढ़ता आतंक,घर से 5 बकरे-बकरियों की चोरी

—संवाददाता—
लखनपुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात वार्ड क्रमांक 2 में गणेश प्रसाद क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुधन के स्वास्थ्य, देखभाल और सुरक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

लखनपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात वार्ड क्रमांक 2 में गणेश प्रसाद क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुधन के स्वास्थ्य, देखभाल और सुरक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।



खड़े ट्रक से 300 लीटर डीजल की चोरी हो चुकी थी। लगातार हो रही इन चोरों की घटनाओं से नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

लोग पुलिस की रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लखनपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गई है। पॉइंट परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। नगरवासी मांग कर रहे हैं कि पुलिस रात्रि गश्त बढ़ाए और चोरों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों।



खनिज न्यास निधि की राशि के दुरुपयोग का आरोप

जहां सड़क ही नहीं, वहां 12 लाख की पुलिया !

■ न सड़क से जुड़ाव, न कोई योजना | ■ सरईपारा की कच्ची सड़क की अनदेखी पर ग्रामीण नाराज | ■ इस्टीमेट में केशर गिट्टी, मौके पर लाल पत्थर का इस्तेमाल | ■ नदी के डुबान क्षेत्र में निर्माण, जांच का अधिकार राजस्व विभाग का | ■ पटवारी हड़ताल पर, जांच कैसे होगी ?

जनता को सड़क चाहिए, निर्माण में पुलिया मिल गई! 12 लाख के काम पर सवाल की बौछार

खनिज न्यास की राशि पर सवाल, नरसिंहपुर में पुलिया निर्माण विवादों में, गुणवत्ता से लेकर स्थल चयन तक उठे सवाल

12 लाख की पुलिया, न सड़क न कनेक्टिविटी! सरईपारा की बदहाल सड़क छोड़ निर्माण पर सवाल

नदी के डुबान क्षेत्र में पुलिया निर्माण का आरोप, खनिज न्यास निधि के इस्तेमाल पर जांच की मांग

केशर गिट्टी की जगह लाल पत्थर इस्तेमाल करने का आरोप, पुलिया निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल

जनपद की जांच पर सवाल, पटवारी हड़ताल से राजस्व जांच की राह मुश्किल, नरसिंहपुर पुलिया विवाद गहतरा

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत मोदीपारा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम नरसिंहपुर में निर्माणधीन पुलिया अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से करीब 12 लाख रुपये की लागत से कराए जा रहे इस निर्माण कार्य की उपयोगिता, निर्माण स्थल के चयन और इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं, स्थानीय वार्ड पंच शानू खान ने आरोप लगाया है कि जिस स्थान पर पुलिया बनाई जा रही है, वहां से आगे न तो कोई सड़क जुड़ती है और न ही निकट भविष्य में

जहां सड़क ही नहीं, वहां पुलिया की उपयोगिता पर सवाल-

पुलिया निर्माण के स्थान को लेकर वार्ड पंच शानू खान ने आपत्ति जताई है, उनका आरोप है कि निर्माण स्थल से आगे सड़क का संपर्क नहीं है, ऐसे में पुलिया किस मार्ग को जोड़ने और किस आबादी को सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है, यह स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी निर्माण कार्य की उपयोगिता केवल उसके बन जाने से साबित नहीं होती, बल्कि यह भी जरूरी है कि वह लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करे, ग्रामीणों की मांग है कि निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन कराया जाए और यह जांचा जाए कि पुलिया स्वीकृत स्थल पर ही बनाई जा रही है या नहीं, साथ ही, योजना के दस्तावेजों में दर्ज उद्देश्य, स्वीकृत प्राक्कलन और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान भी किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खर्च की जा रही राशि जनहित में कितनी उपयोगी साबित होगी।

सड़क निर्माण की कोई स्पष्ट योजना दिखाई दे रही है, ऐसे में सरकारी राशि से हो रहे इस निर्माण का ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा, यह बड़ा सवाल बन गया है, मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि ग्रामीणों के अनुसार गांव के सरईपारा में कच्ची सड़क की स्थिति खराब है, बरसात के दिनों में इस मार्ग पर आवागमन करना मुश्किल हो जाता है, वार्ड पंच का कहना है कि यदि इसी राशि से सरईपारा की सड़क का निर्माण या सुधार कराया जाता, तो ग्रामीणों को अधिक प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता था, अब सवाल यह है कि विकास कार्यों के लिए राशि खर्च करते समय स्थानीय जरूरतों और आम लोगों की सुविधा को कितनी प्राथमिकता दी गई?

निर्माण सामग्री पर भी उठे सवाल- विवाद केवल पुलिया के स्थान तक सीमित नहीं है, वार्ड पंच ने निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं, उनका दावा है कि स्वीकृत इस्टीमेट के

अनुसार केशर की गिट्टी का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मौके पर हाथ से तोड़े गए लाल पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, हालांकि, सामग्री के संबंध में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि अभी सामने आना बाकी है, ऐसे में जरूरी है कि निर्माण स्थल से सामग्री के नमूने लेकर निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप जांच कराई जाए, स्वीकृत प्राक्कलन, निर्माण सामग्री के बिल, गुणवत्ता परीक्षण और कार्य की तकनीकी निगरानी से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण भी किया जाना चाहिए, यदि स्वीकृत सामग्री के स्थान पर मानकों से अलग सामग्री का उपयोग प्रमाणित होता है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

पटवारियों की अनिश्चितकालीन

हड़ताल के बीच कैसे होगी जांच?- ग्रामीणों ने जांच प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं, मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, ऐसे में यदि निर्माण स्थल की राजस्व स्थिति, डुबान क्षेत्र की सीमा या भूमि संबंधी अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक है, तो जांच किस प्रक्रिया से पूरी की

नदी के डुबान क्षेत्र में निर्माण का आरोप, जांच के अधिकार पर भी सवाल

मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निर्माण स्थल नदी के डुबान क्षेत्र में होने की बात कही जा रही है, इस दावे की पुष्टि के लिए स्थल की राजस्व स्थिति, नदी क्षेत्र की सीमा और संबंधित तकनीकी अभिलेखों की जांच आवश्यक है, शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि डुबान क्षेत्र से जुड़े पहलुओं की जांच राजस्व विभाग के माध्यम से कराई जानी चाहिए, न कि केवल जनपद पंचायत की जांच पर निर्भर रहा जाए, यह भी आरोप लगाया गया है कि जनपद पंचायत की ओर से जांच की औपचारिकता पूरी कर ली गई है, हालांकि, जांच में वास्तव में क्या परीक्षण किया गया, किन अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और क्या निष्कर्ष निकाला गया, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है, इसलिए जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक होने से ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

जाएगी? यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है, हालांकि, पटवारियों की हड़ताल के कारण जांच पूरी तरह रुक जाएगी, ऐसे निष्कर्ष बिना विभागीय जानकारी के नहीं निकाला जा सकता, प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि मामले की जांच के लिए कौन-सा अधिकारी या विभाग जिम्मेदार होगा और स्थल की वास्तविक स्थिति

क्या खनिज न्यास निधि की राशि का उपयोग जरूरत के अनुसार हो रहा है?

खनिज न्यास निधि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां के लोगों के हित में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है, ऐसे में इस निधि से कराए जाने वाले प्रत्येक निर्माण की उपयोगिता, गुणवत्ता और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, नरसिंहपुर में करीब 12 लाख रुपये की लागत से बन रही पुलिया को लेकर उठे सवाल के बीच यह स्पष्ट होना चाहिए कि स्थल का चयन किन आधारों पर किया गया, निर्माण से किन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है और क्या काम स्वीकृत तकनीकी मानकों के अनुसार कराया जा रहा है, यदि पुलिया की उपयोगिता को लेकर उठाई गई आपत्तियां सही पाई जाती हैं, तो यह केवल एक निर्माण कार्य का मामला नहीं रहेगा, बल्कि योजना निर्माण और सरकारी राशि के उपयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करेगा, वहीं, यदि निर्माण स्थल और सामग्री स्वीकृत मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं, तो प्रशासन को जांच के निष्कर्षों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

का सत्यापन किस तरह कराया जाएगा, जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि मौके की स्थिति और तकनीकी पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जाए।

कलेक्टर रोकितमा यादव ने कहा... अनियमितता मिली तो कराई जाएगी जांच-इस पूरे मामले में कोरिया कलेक्टर रोकितमा यादव से चर्चा की गई, उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में जांच अत्यंत आवश्यक है, यदि कार्य में कोई अनियमितता है या निर्माण स्वीकृत स्थल के बजाय किसी अन्य स्थान पर कराया जा रहा है, तो इसकी जांच कराई जाएगी और वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा, कलेक्टर के इस आश्वासन के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निर्माण स्थल, सामग्री की गुणवत्ता, स्वीकृत प्राक्कलन और डुबान क्षेत्र से जुड़े

बिंदुओं की जांच किस स्तर पर कराई जाती है, ग्रामीणों की अपेक्षा है कि जांच निष्पक्ष हो, मौके की वास्तविक स्थिति सामने आए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अब निगाहें जांच पर- नरसिंहपुर की निर्माणधीन पुलिया को लेकर उठे सवालों का जवाब आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि निष्पक्ष तकनीकी और राजस्व परीक्षण से ही मिल सकता है, करीब 12 लाख रुपये की लागत वाले इस कार्य में स्थान चयन से लेकर निर्माण सामग्री तक हर पहलू की जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खनिज न्यास निधि से किया जा रहा खर्च ग्रामीणों की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं।



फसल उजाड़ने पर भड़के ग्रामीण, पहुंचे वन विभाग के कार्यालय हुई नोकझोंक

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र के बेलदगी गांव में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि खेती के लिए जंगल में वन विभाग के अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना दिए उनकी टमाटर और जटकी की फसल उजाड़ दी। ग्रामीणों का कहना है कि खेती में लाखों रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन फसल नष्ट होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण वन विभाग पहुंच कर अपनी नाराजगी जताई। मामला 16 अक्टूबर का है, जब वन विभाग की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों की फसलें उखाड़कर फेंक दी गईं। ग्रामीणों के मुताबिक, उन्होंने

बीज, खाद और खेती के अन्य संसाधनों पर लाखों रुपये खर्च किए थे। फसल तैयार होने से पहले ही उसे नष्ट किए जाने से उनकी मेहनत और पूंजी दोनों पर संकट खड़ा हो गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन भूमि पर खेती को लेकर वन विभाग को आपत्ति थी, तो उन्हें पहले नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। इसी कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर नुकसान की जांच के साथ उचित समाधान की मांग की। फिलहाल, जमीन की कानूनी स्थिति, कार्रवाई में अपनाई गई प्रक्रिया और फसल के वास्तविक नुकसान को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। अब देखना होगा कि वन विभाग और प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं।

बरगांव में नशामुक्त युवा विषय पर नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट आयोजित, युवाओं को किया जागरूक

-संवाददाता-

जशपुरनगर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

मेरा युवा भारत, जशपुर (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार) के नेतृत्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ में नशामुक्त युवा विषय पर नेबरहुड

यूथ पार्लियामेंट (पड़ोस युवा संसद) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना तथा विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में मेरा युवा भारत के विवेकानंद यूथ

क्लब एवं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हेमराज सिंह ने प्रोजेक्टर के माध्यम से MY Bharat पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही नशामुक्त भारत अभियान से संबंधित वीडियो दिखाकर विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

सुर-संगीत संघ ने किशोर कुमार को दी सुरमयी श्रद्धांजलि नए युवा कलाकारों को अवसर देना संस्था की सराहनीय पहल : मंजूषा भगत



-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

महान पारवर्गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर सुर-संगीत संघ, अम्बिकापुर के तत्वावधान में स्थानीय कला केंद्र मैदान में 'गाता रहे मेरा दिल, द लीजेंड किशोर दा स्वरांजलि' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगीतमय संध्या में शहर के स्थानीय और नवोदित कलाकारों ने किशोर कुमार के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चली इस संगीतमय महफिल में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, संत गहिर्वा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र लागपाले, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष, एमआईसी सदस्य मनीष सिंह,



वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार बंसल, जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला, महामाया मंडल अध्यक्ष मनोज कंसारी और समलया मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर महापौर मंजूषा भगत ने सुर-संगीत संघ के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शहर में गीत-संगीत से जुड़े कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए। ऐसे आयोजन न केवल संगीत प्रेमियों को एक मंच प्रदान करते हैं, बल्कि नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी देते हैं। उन्होंने कहा कि नए युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना संस्था की सराहनीय पहल है। संत गहिर्वा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र लागपाले ने युवा कलाकारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगीत के क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और कड़ी मेहनत जरूरी है। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने आयोजन को अद्भुत बताते हुए

कहा कि लंबे समय बाद शहर में इस तरह की संगीतमय महफिल सजी है। उन्होंने ऐसे आयोजनों की निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में अतिथि कलाकार गोपाल पांडेय, चंद्र प्रताप सिंह, स्वर्निल जायसवाल और मलय भट्टाचार्य के साथ संजीव वर्मा, संतोष दास सरल तथा अश्वि वार्मा ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। वहीं, नवोदित कलाकार विमल मंदिलवार, उमेश मिश्रा, राधेश्याम मानिकपुरी, नीतेश पांडेय, राकेश शुक्ला, अरुण अग्रवाल, सुप्रिया सिन्हा, हितेश सिंह, अमित तिवारी, रेखा देवांगन, राजकुमार देवांगन, भोला रक्सेल, रितेश दत्तवार, शिवम सिन्हा, शिवराज सिंह, राम मंगेशिया, गीता भूपल, लीला आगरा, सूरज पाठक, लता चौहान, ऋषभ यादव, पूनम प्रजापति, प्रिया सिंह और प्रजावति भात ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुतियों का सिलसिला ऐसा चला कि श्रोता

अंत तक अपनी जगह पर डटे रहे। पूरे आयोजन में संगीत और सुरों की ऐसी छटा बिखरी कि कला केंद्र मैदान देर रात तक तालियों की गूंज से सराबोर रहा। कार्यक्रम का संचालन सुर-संगीत संघ के जिलाध्यक्ष संतोष दास सरल ने किया, जबकि संघ के सचिव राधेश्याम मानिकपुरी ने आधार व्यवस्थापन किया। इस अवसर पर पार्षद शैलेश सिंह, विजय सोनी, शशिकांत जायसवाल, विद्यानंद मिश्रा, सावित्री जायसवाल, प्रियंका चौबे, नीलू गुप्ता, कृष्णानंद तिवारी, विनय अंबट, बुद्धम श्याम, रंजीत सारथी, डॉ. सपन सिन्हा, मंगल पांडेय, अभय तिवारी, तेजेंद्र बग्गा, अनिल मिश्रा, अजय तिवारी, हरिशंकर सिंह, जय गुप्ता, दिनेश शुक्ला, बबलू गुप्ता, अनिश सिंह, अविनाश मंडल, डॉ. राजेश तिवारी, श्रीधर केशरी, शालिनी सिंह, अजय सोनी, जन्मेजय पांडेय, शैलेन्द्र शर्मा, मनोज प्रसाद और अनुराग शुक्ला सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।



महिला आरक्षण में किसे मिलेगा मौका? सक्रिय महिला नेत्रियों और राजनीतिक परिवारों की दवेदारी पर मंथन

शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण के बीच भाजपा-कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल,सक्रिय महिला नेत्रियों को अवसर मिलेगा या परिवार की राजनीतिक विरासत बनेगी आधार?

शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण की असली परीक्षा,टिकट महिला को तो नेतृत्व भी उसी के हाथ?

राजनीतिक विरासत या महिला नेतृत्व? शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण ने खड़े किए बड़े सवाल

टिकट महिला को,फैसले कौन करेगा? शिवपुर-चरचा में महिला नेतृत्व की स्वतंत्रता पर सवाल

कुंती-दीपा से लालमुनि-नीता तक चर्चा, क्या सक्रिय महिला नेत्रियों को मिलेगा अध्यक्ष पद का मौका?

महिला आरक्षण बनाम परिवार की राजनीति,शिवपुर-चरचा में भाजपा-कांग्रेस की अग्निपरीक्षा

महिला अध्यक्ष बनेगी,लेकिन क्या स्वतंत्र रूप से चलाएगी निकाय? शिवपुर-चरचा में उठे सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जिले की नगरीय राजनीति में शिवपुर-चरचा नगर पालिका अध्यक्ष पद का आगामी चुनाव इस बार केवल प्रत्याशी चयन की कवायद तक सीमित नहीं रह गया है,अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद अब राजनीतिक चर्चाओं में एक बड़ा सवाल उभर रहा है की क्या इस अवसर पर उन महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिलेगा,जो वर्षों से संगठन, सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं,या फिर ऐसे परिवारों की महिलाएं आगे आएंगी जिनके पुरुष सदस्य पहले से स्थानीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि दोनों प्रमुख दलों में संभावित महिला प्रत्याशियों को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं,भाजपा में नगर पालिका की प्रथम अध्यक्ष रह चुकी कुंती चक्रधारी और वर्तमान मंडल अध्यक्ष दीपा विश्वकर्मा के नामों की चर्चा है,वहीं कांग्रेस में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव और पूर्व एलडरमैन नीता मिश्रा जैसी महिला नेताओं की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं,इनके अलावा दूसरे संभावित नाम भी सामने आ सकते हैं, दूसरी तरफ महिला आरक्षण के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय पुरुष नेताओं के परिवार की महिलाओं की दवेदारी को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है,ऐसे में सवाल केवल यह नहीं है कि पार्टी किस महिला को अपना प्रत्याशी बनाती है, बल्कि यह भी है कि चुनाव जीतने के बाद उसे नगर पालिका के संचालन और निर्णय प्रक्रिया में कितनी स्वतंत्रता

मिलेगी,महिला आरक्षण से पद पर महिला की भागीदारी सुनिश्चित होती है, लेकिन उस पद की वास्तविक जिम्मेदारी कौन निभाएगा,यह सवाल प्रत्याशी चयन से लेकर निर्वाचित होने के बाद तक महत्वपूर्ण बना रहता है।

महिला सीट ने खोले रास्ते,अब दवेदारी की कसौटी पर संगठन शिवपुर-चरचा में अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला श्रेणी के लिए आरक्षित होने के बाद महिला दवेदारों के लिए चुनावी अवसर खुला है,इस श्रेणी में पात्र महिलाएं अपनी दवेदारी प्रस्तुत कर सकती हैं,अब भाजपा और कांग्रेस के सामने ऐसे उम्मीदवार का चयन करने की चुनौती है जो संगठन के साथ जुड़ाव, सार्वजनिक सक्रियता, स्थानीय समस्याओं की समझ और नेतृत्व की भूमिका निभाने की क्षमता रखती हो,स्थानीय राजनीतिक चर्चा में एक तरफ ऐसे महिला चेहरों की बात हो रही है, जो पहले से संगठन में जिम्मेदारियां निभा रही हैं, दूसरी तरफ उन महिलाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनकी राजनीतिक पहचान परिवार के पुरुष सदस्यों की सक्रियता के कारण बनी है या जिन्हें अब परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के सहारे आगे लाने की चर्चा है,यहां किसी महिला की राजनीतिक योग्यता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसका परिवार राजनीति में कितना सक्रिय रहा है,परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होना अपने आप में अयोग्यता नहीं है, ठीक उसी तरह केवल सक्रिय राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना किसी महिला की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण भी नहीं है,असली कसौटी यह होगी कि उम्मीदवार की अपनी राजनीतिक समझ, जनसंपर्क,संगठनात्मक अनुभव और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता क्या है, राजनीतिक दलों को टिकट वितरण के दौरान इन्हें पहचानने पर स्पष्टता रखनी होगी।

भाजपा के सामने विकल्प : कुंती चक्रधारी या दीपा विश्वकर्मा? भाजपा में महिला नेतृत्व की चर्चा होती है

तो कुंती चक्रधारी और दीपा विश्वकर्मा के नाम सामने आते हैं,कुंती चक्रधारी शिवपुर-चरचा नगर पालिका की प्रथम अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके पूर्व कार्यकाल का अनुभव उनकी संभावित दवेदारी के संदर्भ में चर्चा का विषय है,वहीं दीपा विश्वकर्मा वर्तमान में भाजपा की मंडल अध्यक्ष हैं,संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाने के कारण उनका नाम भी संभावित महिला नेतृत्व की चर्चा में शामिल है,दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है,

सरकार का नया नियम : परोक्ष प्रतिनिधित्व पर रोक

महिला जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्र भूमिका का सवाल अब केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2026 में नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों को उनके परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन किया, नए प्रावधान के अनुसार पति, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या अन्य निकट पारिवारिक सदस्य को निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के साथ नगरीय निकायों में लागू किया गया, इस नियम का सीधा संबंध निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की आधिकारिक भूमिका से है, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य की हर प्रकार की व्यक्तिगत भागीदारी स्वतः निषिद्ध हो गई है, नियम का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिला प्रतिनिधि की जगह परिवार का कोई सदस्य औपचारिक रूप से उसका परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक बनकर काम नहीं कर सकता, शिवपुर-चरचा के संदर्भ में यह मुद्दा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांगने वाले कुछ संभावित उम्मीदवारों के परिवार के पुरुष सदस्य पहले से स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ऐसे में मतदाताओं के सामने यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि इन परिवारों की कोई महिला अध्यक्ष बनती है, तो वह स्वयं कितनी सक्रियता से निकाय की जिम्मेदारी निभाएगी, इसका उत्तर केवल किसी घोषणा या आश्वासन से नहीं मिलेगा, यह निर्वाचित प्रतिनिधि के वास्तविक कामकाज, निर्णय प्रक्रिया में उसकी भागीदारी और जनता के प्रति जवाबदेही से स्पष्ट होगा।

एक ओर पूर्व अध्यक्ष के रूप में निकाय के कामकाज का अनुभव है, तो दूसरी ओर वर्तमान संगठनात्मक जिम्मेदारी का पहलू है,इनके अतिरिक्त भी भाजपा में ऐसी महिला कार्यकर्ता हो सकती हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी दवेदारी रखना चाहती हों,ऐसे में भाजपा के सामने सवाल यह होगा कि पार्टी किस आधार पर उम्मीदवार का चयन करती है,क्या पूर्व निकाय अनुभव को अधिक महत्व मिलेगा? क्या वर्तमान

संगठनात्मक जिम्मेदारी और सक्रियता को प्राथमिकता दी जाएगी? या फिर स्थानीय समीकरणों और दूसरे संभावित दवेदारों के बीच सहमति के आधार पर कोई नया नाम सामने आएगा? फिलहाल पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसलिए कुंती चक्रधारी या दीपा विश्वकर्मा में से किसी एक को निश्चित उम्मीदवार मानना जटिलवाजी होगी, लेकिन इन नामों की चर्चा ने महिला नेतृत्व को लेकर पार्टी की संभावित रणनीति पर ध्यान जरूर केंद्रित किया है।

कांग्रेस में लालमुनि यादव और नीता मिश्रा के नाम भी महत्वपूर्ण

कांग्रेस के सामने भी महिला प्रत्याशी का चयन कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है, स्थानीय राजनीतिक चर्चा में लालमुनि यादव और नीता मिश्रा जैसे नामों का उल्लेख किया जा रहा है, लालमुनि यादव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस वजह से उनके नाम के साथ निकाय संचालन का पूर्व अनुभव जुड़ा हुआ है, नीता मिश्रा पूर्व एलडरमैन रही हैं और निकाय के कामकाज की जिम्मेदारी वास्तव में कांग्रेस के अनुभव के संदर्भ में की जा रही है, इन नामों के सामने आने से कांग्रेस के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी अपने मौजूदा और पूर्व महिला जनप्रतिनिधियों के अनुभव का कितना उपयोग करती है,इसके साथ ही संगठन में सक्रिय दूसरी महिला कार्यकर्ताओं के लिए अवसर का प्रश्न भी बना हुआ है, कांग्रेस के भीतर किसे टिकट मिलेगा,इस संबंध में अंतिम निर्णय सामने आने तक किसी दवेदारी को निश्चित

नहीं कहा जा सकता,लेकिन अगर पार्टी महिला आरक्षण को महिला नेतृत्व बढ़ाने का अवसर मानती है,तो उसे सभी संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन एक समान और स्पष्ट मानदंडों पर करना होगा,राजनीति में अनुभव महत्वपूर्ण है,लेकिन अनुभव के साथ वर्तमान सक्रियता, स्थानीय लोगों से संपर्क और भविष्य की कार्ययोजना भी मायने रखती है,इसलिए किसी भी संभावित उम्मीदवार की दवेदारी का मूल्यांकन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

परिवार की राजनीतिक विरासत या महिला की अपनी पहचान?

शिवपुर-चरचा की चुनावी चर्चा में सबसे प्रमुख सवाल यही बन रहा है कि महिला आरक्षण का लाभ किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा,यदि कोई महिला लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है और संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाती रही है,तो उसके पास अपनी राजनीतिक पहचान और अनुभव प्रस्तुत करने का आधार है,दूसरी ओर,किसी राजनीतिक परिवार की महिला यदि पहली बार चुनाव मैदान में आती है,तो उसका परिवार से जुड़ाव अपने आप में गलत नहीं कहा जा सकता,कई बार परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अवसर भी देती है,लेकिन ऐसी महिला का मूल्यांकन भी उसकी अपनी सक्रियता,नागरिकों से संपर्क और नेतृत्व की तैयारी के आधार पर ही होना चाहिए, समस्या तब पैदा होती है जब उम्मीदवार के नाम पर चुनाव तो लड़ा जाए,लेकिन निर्णय लेने,अधिकारियों से संवाद करने और निकाय के कामकाज की जिम्मेदारी वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति संभाले,इससे निर्वाचित प्रतिनिधि की जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व दोनों प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि वे उम्मीदवार चयन के समय केवल नाम और पारिवारिक पृष्ठभूमि न देखें,बल्कि यह भी समझें कि महिला प्रत्याशी स्वयं इस जिम्मेदारी के लिए कितनी तैयार है और निर्वाचित होने के बाद उसकी अपनी भूमिका क्या होगी।

अब दोनों दलों के जिलाध्यक्षों के निर्णय पर निगाह...

शिवपुर-चरचा में भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन आने वाले चुनाव की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी,दोनों दलों के जिलाध्यक्षों और संगठन के अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों को संभावित नामों पर विचार करते समय कई पहलुओं का संतुलन बनाना होगा,भाजपा के सामने कुंती चक्रधारी,दीपा विश्वकर्मा और अन्य संभावित महिला दवेदारों के बीच विचार करने का अवसर है,कांग्रेस में लालमुनि यादव,नीता मिश्रा और अन्य महिला नेताओं के नाम चर्चा में हैं,अंतिम फैसला पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया,स्थानीय समीकरणों और प्रत्याशी चयन के मानदंडों के आधार पर ही होगा,लेकिन टिकट की घोषणा से पहले ही महिला नेतृत्व को लेकर उठे सवालों ने दोनों दलों के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी सामने रख दी है,उया पार्टी ऐसी महिला को मौका देगी जिसकी अपनी पहचान और संगठनात्मक भूमिका स्पष्ट है? क्या परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाली महिला को अवसर मिलने पर उसकी स्वतंत्र जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाएगा? और क्या चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि वास्तव में स्वयं निकाय का संचालन करेगी? इन सवालों का उत्तर किसी एक नाम से नहीं, बल्कि टिकट चयन की प्रक्रिया और चुनाव के बाद के कामकाज से मिलेगा।

आरक्षण के बाद अब स्वतंत्र नेतृत्व की बारी-शिवपुर

चरचा नगर पालिका का आगामी चुनाव महिला आरक्षण के साथ-साथ स्थानीय राजनीति में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी पर चर्चा का अवसर भी बन गया है,भाजपा में कुंती चक्रधारी और दीपा विश्वकर्मा जैसे नामों की चर्चा है,तो कांग्रेस में लालमुनि यादव और नीता मिश्रा के नाम सामने आते हैं,इसके अतिरिक्त दूसरी संभावित महिला दवेदारों की भूमिका भी टिकट चयन के दौरान महत्वपूर्ण हो सकती है,राजनीतिक दलों के सामने चुनौती केवल महिला प्रत्याशी घोषित करने की नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाने की भी है जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सके,महिला आरक्षण का असली अर्थ तभी पूरा होगा,जब टिकट पाने वाली महिला केवल किसी परिवार की राजनीतिक पहचान का विस्तार नहीं,बल्कि अपनी भूमिका,निर्णय और जवाबदेही के साथ निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सामने आए,अब निगाहें भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चयन पर हैं,उनके निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि शिवपुर-चरचा में महिला आरक्षण के अवसर को किस तरह देखा गया-केवल चुनावी श्रेणी के रूप में या महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में।



-संवाददाता- बलरामपुर, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

आधार से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में आयोजित तीन दिवसीय विकासखण्ड स्तरीय विशेष आधार शिविर का आज समापन हुआ। चिपस के माध्यम से 14 से 16 अक्टूबर तक विकासखण्ड बलरामपुर,शंकरगढ़ एवं

कुसुमी के जनपद पंचायत कार्यालयों में लगे इन शिविरों में कुल 686 आधार सेवाओं का निराकरण किया गया। ग्रामीणों को अपने ही विकासखण्ड में यह सुविधा मिलने से बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे। शिविर के पहले दिन 14 अक्टूबर को बलरामपुर में 415, 15 अक्टूबर को शंकरगढ़ में 79 तथा अंतिम दिन कुसुमी में 192 सेवाएं प्रदान की गईं। सबसे अधिक

254 प्रकरण उपनाम सुधार और 156 बायोमेट्रिक अपडेट के रहे। इसके अलावा 70 जन्मतिथि सुधार,58 नाम व वर्तनी सुधार,39 नए आधार पंजीयन,28 मोबाइल नंबर अपडेट, 28 जेंडर सुधार, 22 बायोमेट्रिक मिस्मैच,12 आधार कैसिल,8 पता परिवर्तन तथा 7 अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।



73 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जटिल कूल्हे की सर्जरी सफल

जब सूरजपुर में इतनी बड़ी सर्जरी संभव है तो प्रसव के ऑपरेशन के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता क्यों?



प्रसव के लिए निजी अस्पतालों की मजबूरी कब होगी खत्म?

■ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में प्रयास

■ सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम को सफलता

■ दूसरे शहरों में इलाज के लिए जाने की मजबूरी कम

■ क्या प्रेमनेसी जैसी सर्जरी भी जिला अस्पताल में संभव नहीं?

73 वर्षीय महिला की जटिल सर्जरी सफल, फिर प्रसव ऑपरेशन के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता क्यों?

कूल्हे की जटिल सर्जरी सरकारी अस्पताल में संभव, तो प्रसव ऑपरेशन की सुविधा पर सवाल क्यों?

जटिल सर्जरी सरकारी अस्पताल में, फिर प्रसव के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता क्यों?

गंभीर सर्जरी सरकारी अस्पताल में संभव तो प्रसूता को स्थानीय स्तर पर ऑपरेशन की सुविधा कितनी सुलभ? स्वास्थ्य सेवाओं के दावों के बीच मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा जरूरी

सर्जरी में सफलता के दावे, फिर प्रसव के लिए निजी अस्पतालों का रुख क्यों?

सूरजपुर जिला अस्पताल में जटिल सर्जरी सफल, अब मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की बारी...

स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में बेहतर इलाज की पहल, प्रसव ऑपरेशन की सुविधा पर भी उठें सवाल

73 वर्षीय बुजुर्ग की सर्जरी से बढ़ी उम्मीद, प्रसव सेवाओं की हकीकत जानना भी जरूरी

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बीच सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम के नेतृत्व में चिकित्सकीय टीम को सफलता

अब प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता और रेफरल व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत

उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और आपातकालीन व्यवस्था की भी उसी गंभीरता से दोमोखा की जाएगी? यह सवाल किसी एक सफल ऑपरेशन की उपलब्धि को कमतर आंकने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक तस्वीर सामने रखने के लिए महत्वपूर्ण है, सरकारी अस्पताल में जटिल सर्जरी की सफलता निश्चित रूप से उत्साहजनक है, लेकिन आम जनता के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक कसौटी यह भी है कि प्रसव जैसी संवेदनशील स्थिति में गर्भवती महिला को समय पर सुरक्षित उपचार, आवश्यक विशेषज्ञता और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन की सुविधा मिल रही है या नहीं।

दोनों कूल्हों में खराबी और खून की कमी फिर भी सफल रही सर्जरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओड़िशा निवासी 73 वर्षीय श्रीमती राजकुमारी दोनों कूल्हों में खराबी की समस्या से पीड़ित थीं। उपचार के लिए जिला अस्पताल के हड्डी रोग विभाग पहुंचने पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय साहू ने उनकी प्रारंभिक जांच कराई और एक्स-रे कराया, जांच में दोनों कूल्हों में खराबी की पुष्टि हुई, इसके साथ ही शरीर में खून की कमी भी पाई गई, जिससे ऑपरेशन से पहले मरीज की स्थिति को स्थिर करना और आवश्यक उपचार देना चुनौतीपूर्ण था, मरीज की स्थिति को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम के नेतृत्व में आवश्यक उपचार और सर्जरी से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, मरीज को सज्जिल वार्ड में भर्ती कर चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया, नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से स्वास्थ्य में सुधार होने और ऑपरेशन के लिए उपयुक्त स्थिति बनने के बाद निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार ने आवश्यक जांच की, इसके बाद सर्जरी की तिथि निर्धारित की गई, यह मामला बताता है कि किसी जटिल ऑपरेशन की सफलता केवल सर्जन की भूमिका तक सीमित नहीं होती। मरीज की प्रारंभिक जांच, ऑपरेशन से पहले की तैयारी, निश्चेतना संबंधी आकलन, नर्सिंग देखभाल, ऑपरेशन थिएटर की उपलब्धता और पूरी टीम के बीच तालमेल भी महत्वपूर्ण होता है।

डॉ. अजय साहू और ऑपरेशन थिएटर टीम की अहम भूमिका

निर्धारित तिथि पर ऑपरेशन थिएटर प्रभारी नविदा परवीन के नेतृत्व में सर्जरी की आवश्यक तैयारियां पूरी की गई, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय साहू के साथ श्रीमती नविदा परवीन, मयंक राजवाड़े, सीमा देवाना, अटी टेक्नीशियन बोधन राजवाड़े और प्रियंका राजवाड़े ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सर्जरी के दौरान निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार ने मरीज की स्थिति स्थिर बनाए रखने में अहम योगदान दिया, ऑपरेशन थिएटर के अन्य सहयोगी कर्मचारियों ने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। पूरी टीम के समन्वित प्रयास से जटिल सर्जरी

सफलतापूर्वक संभर हुई, डॉ. अजय साहू के अनुसार, मरीज की उम्र और दोनों कूल्हों में खराबी के कारण यह मामला चुनौतीपूर्ण था, इसके बावजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, अस्पताल से मिली जानकारी के

करीब पड़ता है? क्या इसका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, ऑपरेशन थिएटर की उपलब्धता, निश्चेतना विशेषज्ञ की अनुपलब्धता, आवश्यक संसाधनों की कमी या किसी अन्य चिकित्सकीय परिस्थिति से जुड़ा है? इन सवालों का जवाब केवल दावों या अनुमान के आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसके लिए जिला अस्पताल में होने वाले प्रसवों, सिजेरियन ऑपरेशनों, रेफर किए गए मामलों और रेफरल के कारणों के आंकड़ों की समीक्षा आवश्यक है, अस्पताल प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यहां प्रसूति संबंधी ऑपरेशन की सुविधा किस स्तर पर उपलब्ध है और किन परिस्थितियों में मरीजों को उच्चतर केंद्र भेजना पड़ता है, यह भी समझना जरूरी है कि हर गर्भवती महिला को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। सामान्य प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन का निर्णय मां तथा शिशु की चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर लिया जाता है, इसलिए लक्ष्य ऑपरेशन की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि जहां ऑपरेशन जरूरी हो वहां समय पर सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराना होना चाहिए।

निजी अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं मरीज? सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता का उद्देश्य आम नागरिकों को सुलभ और किफायती उपचार देना है, इसके बावजूद यदि गर्भवती महिलाओं का रुख करना पड़ता है, तो इसके कारणों की पड़ताल जरूरी है, क्या सरकारी अस्पताल में प्रसूति विशेषज्ञ और निश्चेतना विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? क्या आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन के लिए आवश्यक टीम हर समय तैयार रहती है? क्या रक्त की उपलब्धता, नवजात शिशु की देखभाल और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय उपचार की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या मरीजों को समय पर जानकारी और उचित रेफरल सुविधा मिलती है? इन सवालों का जवाब अस्पताल के वास्तविक रिकॉर्ड और मरीजों के अनुभवों से ही सामने आ सकता है, निजी अस्पताल में उपचार लेने वाले प्रत्येक मरीज के मामले में यह मान लेना उचित नहीं होगा कि सरकारी अस्पताल ने सुविधा देने से इनकार किया या वहां व्यवस्था नहीं थी, कई बार मरीज की स्थिति, विशेषज्ञता की जरूरत या उच्चतर केंद्र में उपचार की आवश्यकता भी रेफरल का कारण हो सकती है, लेकिन यदि किसी मामले में जरूरी सुविधा सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज को बाहर जाना पड़ता है, तो उस कमी की पहचान कर उसे दूर करना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रसूति सेवाओं के मामले में समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक दौड़भाग, आर्थिक बोझ और उपचार में देरी से बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की नियमित समीक्षा जरूरी है।

गंभीर सर्जरी संभव तो प्रसव ऑपरेशन की सुविधा पर सवाल क्यों?

जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला की जटिल कूल्हे की सर्जरी की सफलता के बाद मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर चर्चा स्वाभाविक है, प्रसव के दौरान कुछ महिलाओं को सामान्य प्रसव के बजाय सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रशिक्षित निश्चेतना टीम, ऑपरेशन थिएटर, आवश्यक उपकरण, दवाइयां और जैविकीय घंटे उपलब्ध आपातकालीन व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में सवाल यह है कि सूरजपुर जिला अस्पताल में प्रसव संबंधी ऑपरेशन की सुविधा कितनी नियमित और सुलभ है? यदि गर्भवती महिला को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या उसे जिला अस्पताल में समय पर उपचार मिल पाता है? किन परिस्थितियों में मरीजों को निजी अस्पतालों या दूसरे शहरों में रेफर

करना पड़ता है? क्या इसका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, ऑपरेशन थिएटर की उपलब्धता, निश्चेतना विशेषज्ञ की अनुपलब्धता, आवश्यक संसाधनों की कमी या किसी अन्य चिकित्सकीय परिस्थिति से जुड़ा है? इन सवालों का जवाब केवल दावों या अनुमान के आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसके लिए जिला अस्पताल में होने वाले प्रसवों, सिजेरियन ऑपरेशनों, रेफर किए गए मामलों और रेफरल के कारणों के आंकड़ों की समीक्षा आवश्यक है, अस्पताल प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यहां प्रसूति संबंधी ऑपरेशन की सुविधा किस स्तर पर उपलब्ध है और किन परिस्थितियों में मरीजों को उच्चतर केंद्र भेजना पड़ता है, यह भी समझना जरूरी है कि हर गर्भवती महिला को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। सामान्य प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन का निर्णय मां तथा शिशु की चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर लिया जाता है, इसलिए लक्ष्य ऑपरेशन की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि जहां ऑपरेशन जरूरी हो वहां समय पर सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराना होना चाहिए।

निजी अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं मरीज?

सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता का उद्देश्य आम नागरिकों को सुलभ और किफायती उपचार देना है, इसके बावजूद यदि गर्भवती महिलाओं का रुख करना पड़ता है, तो इसके कारणों की पड़ताल जरूरी है, क्या सरकारी अस्पताल में प्रसूति विशेषज्ञ और निश्चेतना विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? क्या आपातकालीन सिजेरियन ऑपरेशन के लिए आवश्यक टीम हर समय तैयार रहती है? क्या रक्त की उपलब्धता, नवजात शिशु की देखभाल और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय उपचार की व्यवस्था पर्याप्त है? क्या मरीजों को समय पर जानकारी और उचित रेफरल सुविधा मिलती है? इन सवालों का जवाब अस्पताल के वास्तविक रिकॉर्ड और मरीजों के अनुभवों से ही सामने आ सकता है, निजी अस्पताल में उपचार लेने वाले प्रत्येक मरीज के मामले में यह मान लेना उचित नहीं होगा कि सरकारी अस्पताल ने सुविधा देने से इनकार किया या वहां व्यवस्था नहीं थी, कई बार मरीज की स्थिति, विशेषज्ञता की जरूरत या उच्चतर केंद्र में उपचार की आवश्यकता भी रेफरल का कारण हो सकती है, लेकिन यदि किसी मामले में जरूरी सुविधा सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज को बाहर जाना पड़ता है, तो उस कमी की पहचान कर उसे दूर करना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रसूति सेवाओं के मामले में समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक दौड़भाग, आर्थिक बोझ और उपचार में देरी से बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की नियमित समीक्षा जरूरी है।

सफलता के साथ जवाबदेही का सवाल भी जरूरी

73 वर्षीय महिला की सफल कूल्हे की सर्जरी सूरजपुर जिला अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उत्साहजनक उपलब्धि है, इस सफलता के लिए सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम के नेतृत्व में कार्यरत टीम और ऑपरेशन में शामिल सभी कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा, ऐसे प्रयासों से मरीजों को अपने जिले में उपचार मिलने की उम्मीद बढ़ती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती का आकलन केवल कुछ सफल ऑपरेशनों से नहीं, बल्कि आम नागरिक को मिलने वाली सभी आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता से होना चाहिए, बुजुर्गों की सर्जरी के साथ गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव सेवा भी उनकी ही महत्वपूर्ण है, सरकारी अस्पताल में यदि जटिल ऑपरेशन की व्यवस्था संभव है, तो प्रसव संबंधी आवश्यक ऑपरेशन की सुविधा को लेकर भी स्पष्ट स्थिति सामने आनी चाहिए, अब सवाल यह है कि जिला अस्पताल सूरजपुर में प्रसूति संबंधी ऑपरेशन की वास्तविक स्थिति क्या है, कितने मरीजों को निजी अस्पतालों या दूसरे शहरों में रेफर किया जाता है और इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं? इन सवालों पर तथ्य आधारित समीक्षा होने से यह स्पष्ट होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के प्रयासों का लाभ आम जनता तक किस सीमा तक पहुंच रहा है, जनता की अपेक्षा स्पष्ट है कि सरकारी अस्पताल में गंभीर सर्जरी की सफलता के साथ प्रसव जैसी जरूरी सेवाएं भी सुरक्षित, सुलभ और भरोसेमंद बनें, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और जिला अस्पताल प्रबंधन के सामने चुनौती यही है कि उपलब्धियों को व्यापक स्वास्थ्य सुधार में बदला जाए, ताकि जरूरतमंद मरीजों को अनावश्यक रूप से निजी अस्पतालों की ओर न जाना पड़े और हर मरीज को उसकी चिकित्सकीय जरूरत के अनुरूप समय पर उपचार मिल सके।



पत्नी खुद दावेदार, अजीत लकड़ा का संदेश- 'टिकट एक को, लेकिन सब साथ रहेंगे!'

अजीत लकड़ा की पोस्ट से सियासी सवाल: पत्नी भी दावेदार, फिर सबको साथ रखने का भरोसा कितना?

'दावेदार पांच, टिकट एक'—अजीत लकड़ा की पोस्ट चर्चा में, पत्नी भी टिकट की दौड़ में...

टिकट की दावेदारी पत्नी की, एकजुटता का संदेश अजीत लकड़ा का—असली परीक्षा टिकट के बाद!

पत्नी दावेदार, अजीत का एकजुटता संदेश!

—संवाददाता—
चरचा/कोरिया, 17 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

शिवपुर-चरचा नगर पालिका में कांग्रेस के प्रत्याशी चयन को लेकर जारी रस्साकशी के बीच पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजीत लकड़ा की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक चर्चा को एक नया विषय दे दिया है, अजीत लकड़ा ने फेसबुक पर लिखा की दावेदार पाँच, टिकट एक को मिलेगा, लेकिन सब साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पोस्ट के साथ पांच महिलाओं की तस्वीर भी साझा की गई है, पहली नजर में यह संदेश पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने और टिकट के लिए दावेदारी कर रहे नेताओं को चुनाव के दौरान साथ रहने का संकेत देता है, लेकिन इस संदेश के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है कि क्या टिकट की घोषणा के बाद भी कांग्रेस के सभी दावेदार और उनके समर्थक वास्तव में एकजुट रहेंगे? नगर पालिका अध्यक्ष पर के लिए कई नामों की चर्चा है, लेकिन अधिकृत

टिकट अंततः किसी एक को ही मिलना है, टिकट मिलने से पहले सभी दावेदारों का पार्टी के प्रति भरोसा जताना और टिकट नहीं मिलने के बाद भी उसी भावना के साथ संगठन के साथ खड़े रहना—दो अलग-अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर एकजुटता का संदेश देना जितना आसान है, उसे चुनावी मैदान में व्यवहार में उतारना उतनी ही बड़ी चुनौती है, शिवपुर-चरचा की पिछली चुनावी राजनीति को लेकर भी यही सवाल उठता रहा है कि क्या कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों से पूरी तरह उबर पाई है? स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं में पार्टी के भीतर की असहमति और अलग-अलग गुटों की भूमिका को चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जाता है, हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति के पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराने के लिए ठोस तथ्यों की जरूरत होगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि किसी भी दल के लिए अपनी समन्वय चुनावी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अजीत

लकड़ा की पोस्ट को पार्टी के भीतर शांति और एकजुटता बनाए रखने की अपील के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अब निगाह इस बात पर रहेगी कि टिकट घोषित होने के बाद यह संदेश कितनी मजबूती से जमीन पर दिखाई देता है, क्या टिकट से वंचित दावेदार अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे? क्या उनके समर्थक भी उसी तरह साथ खड़े होंगे? और क्या पुराने मतभेद चुनावी प्रतिस्पर्धा के बीच पीछे छूट पाएंगे? क्योंकि एकजुटता का संदेश देना और वास्तव में एकजुट रहना—दोनों में बड़ा अंतर है, कांग्रेस के लिए असली परीक्षा फेसबुक पोस्ट के शब्दों से आगे, टिकट की घोषणा के बाद शुरू होगी, पार्टी के सभी दावेदार यदि अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े रहते हैं, तो एकजुटता का यह संदेश व्यवहार में भी दिखाई देगा, लेकिन यदि टिकट के बाद असंतोष सामने आता है, तो यही पोस्ट राजनीतिक चर्चा में फिर सवालों के घेरे में आ सकती है।

एकजुटता की अपील के बीच अजीत लकड़ा की अपनी पत्नी भी दावेदार

अजीत लकड़ा की फेसबुक पोस्ट इसलिए भी चर्चा का विषय है, क्योंकि टिकट की दौड़ में उनकी पत्नी का नाम भी दावेदार के रूप में सामने आ रहा है, ऐसे में उनका यह कहना कि दावेदार पांच, टिकट एक को मिलेगा, लेकिन सब साथ रहेंगे अपने आप में कई राजनीतिक सवाल खड़े करता है, क्या यह संदेश सभी दावेदारों को साथ लेकर चलने की ईमानदार अपील है, या टिकट की घोषणा से पहले संभावित असंतोष को साधने की कोशिश? पिछला पोस्ट के पीछे की मंशा को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब पोस्ट लिखने वाले की पत्नी स्वयं दावेदारी की दौड़ में हों, तब एकजुटता का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सवाल यह भी है कि यदि टिकट अजीत लकड़ा की पत्नी को नहीं मिलता, तो क्या वे और उनके समर्थक उसी मजबूती से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े रहेंगे? और यदि टिकट उनकी पत्नी को मिलता है, तो क्या बाकी दावेदार भी बिना किसी असंतोष के उनके पक्ष में चुनावी मैदान में उतरेंगे? एकजुटता की असली परीक्षा पोस्ट पर लिखे शब्दों से नहीं, टिकट घोषित होने के बाद के राजनीतिक व्यवहार से होगी।

